पोषण अभियान पर प्रथम राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कल

प्रविष्टि तिथि: 19 MAR 2018 3:54PM by PIB Delhi

पोषण अभियान पर सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी वाली प्रथम कार्यशाला कल प्रवासी भारतीय केंद्र, नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी । पोषण अभियान पर एक समग्र अनुकूलन मुहैया कराने, अभियान के मुख्य घटकों को समझाने, इस्तेमाल में आने वाले सॉफ्टवेयर के उपयोग की जानकारी देने, एवं बेहतर पोषण संबंधी परिणाम देने के लिये अभियान के कार्यान्वयन में विभिन्न मंत्रालयों के बीच सम्मिलन बढ़ाने के लिये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी से इस एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है ।

कार्यशाला कल सुबह 9:30 बजे शुरू होगी एवं निम्न छह सत्रों में विभाजित होगीः

पहला सत्रः ई- इन्क्रीमेंटल लर्निंग एप्रोच एवं अर्ली चाइल्डहुड केयर एण्ड एज्युकेशन मॉड्यूल का लोकार्पण

द्वितीय सत्रः पोषण अभियान के प्रमुख घटक

तीसरा सत्रः पोषण के उन्नत परिणामों के लिये सम्मिलन

चौथा सत्रः पोषण अभियान के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये सहक्रियता का निर्माण

पांचवा सत्रः साझेदारियों का निर्माण

छठा सत्रः भविष्य का मार्ग

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पांच ई-इन्क्रीमेण्टल लर्निंग एप्रोच पाठ्यक्रम एवं दो अर्ली चाइल्हुड केयर एण्ड एज्युकेशन सॉफ्टवेयर मॉड्यूल का शुभारंभ भी कर रहा है । ई-आईएलए एक ऑनलाइन सिस्टम है जहां कार्यक्रम के पदाधिकारी विधिपूर्वक एवं अविरत क्षमता निर्माण के ज़रिये हर लक्ष्य की निरंतर सही ढंग से योजना बनाना एवं उसका निष्पादन करना सीख कर और अधिक प्रभावी बन जाएंगे । ईसीसीई मॉड्यूल का उद्देश्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिये प्रशिक्षकों को मार्गदर्शन देना है ताकि वह उचित ईसीई गतिविधियों की योजना बनाने एवं उनका संचालन करने योग्य हो जाएं ।

सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिव/ सचिव/ उनके प्रतिनिधि कार्यशाला में भाग लेंगे । पोषण संबंधी उन्नत परिणामों के सम्मिलन पर आयोजित सत्रों के संबोधन के लिये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पेयजल एवं स्वच्छता, एवं ग्रामीण विकास मंत्रालयों के सचिवों का आना भी तय किया गया है ।

प्रधानमंत्री ने दिनांक 8 मार्च 2018 को झुंझुनू में पोषण अभियान की शुरुआत की थी । वर्ष 2017-18 से प्रारंभ कर 9046.17 करोड़ रुपये के तीन वर्षीय बजट से पोषण अभियान की आधारशिला रखी गई है । सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में अभियान को चरणबद्ध ढंग से कार्यान्वित किया जाएगा ।

अभियान के निष्पादन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये अल्पविकास की प्रबलता के घटते हुए क्रम में 315 ज़िलों की पहचान की गई है । दिनांक 15 मार्च 2018 को इन ज़िलों के साथ अनुकूलन के लिये वीडियो-कॉफ्रेंसिंग भी आयोजित की गई ।

पोषण अभियान के अंतर्गत राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां शुरू की जानी है :

राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर कन्वर्जेंस एक्शन प्लान का क्रियान्वयन

राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा स्मार्टफोन, विकास मापने के उपकरणों एवं टैबलेट का अधिग्रहण

आईसीडीएस-सीएएस (कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर) का प्रयोग प्रारंभ करना

आईएलए (इन्क्रीमेण्टल लर्निंग एप्रोच) एवं सीबीई (कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स) का कार्यान्वयन

इस वर्ष अम्बेडकर जयंती (14 अप्रैल) के अवसर पर पूरे देश में ग्राम पंचायतें स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के मुद्दों के साथ साथ पोषण संबंधी आयामों एवं उनके क्रियान्वयन पर चर्चा के लिये बैठकें आयोजित करेंगी । दिनांक 14 अप्रैल 2018 को ग्राम पंचायतों की बैठकें आयोजित करवाने के लिये आवश्यक दिशानिर्देश जारी करने के लिये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव श्री राकेश श्रीवास्तव एवं पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री अमरजीत सिन्हा द्वारा एक संयुक्त पत्र सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को दिनांक 16 मार्च 2018 को भेजा गया है ।

पूरे देश में पोषण अभियान को रफ्तार से क्रियान्वित करने हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को संवेदनशील बनाने एवं सहायता प्रदान करने के लिये इस कार्यशाला का आयोजन कर रहा है ।

***

वीके/एएम/एबी/एमएस-7118

(रिलीज़ आईडी: 1525355) आगंतुक पटल : 31